ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

भारत में बेरोजगार एवं बेरोजगारी की समस्या

Unemployed and Unemployment Problem In India

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

सत्यवीर सिंह
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
डॉ0 बी0 आर0 अम्बेड़कर
राजकीय महाविद्यालय, अनौंगी,
कन्नौज, उ०प्र० भारत

सारांश

बेरोजगारी की समस्या ने पूरे विश्व को उद्धोलित कर रखा है। भारत समेत विश्व के अनेक देशों में समुचित रोजगारी की माँग प्रभावी रुप से उठती रही है। शिक्षा का अभाव , रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन सम्बन्धी समस्याएं कुछ ऐसे कारक है जो बेरोजगारी का कारण बनती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह केवल देश के आर्थिक विकास में खडी प्रमुख बाधाओं में से ही एक नही बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। पूर्ण बेरोजगारी के साथ साथ अल्पबेरोजगारी तथा प्रछन्न बेरोजगारी की समस्या समान रुप से गम्भीर है। बेरोजगारी की समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता यदि इस समस्या का सही समाधान न निकाला गया तो यह समस्या कई अन्य समस्याओं के उदय होने का कारण बन जायेगी।

देश हित में यह अति आवश्यक है कि इस समस्या का प्रभावी निदान इस प्रकार खोजा जाय जिससे कि भविष्य में भी विकराल न हो सके।

The problem of unemployment has rocked the whole world. Demand for proper employment has been effectively raised in many countries of the world including India. Lack of education, lack of employment opportunities and performance problems are some of the factors that lead to unemployment. The government needs to take effective steps to eliminate this problem. One of the main problems facing developing countries is unemployment. It is not only one of the major hurdles in the economic development of the country, but also has many negative effects on the individual and the whole society simultaneously. Along with total unemployment, the problem of underemployment and hidden unemployment is equally serious. The problem of unemployment cannot be ignored, if the right solution to this problem is not found, then this problem will become the reason for the rise of many other problems.

In the interest of the country, it is very important that an effective diagnosis of this problem is found in such a way that it does not become too vicious in the future.

मुख्य शब्द : बेरोजगार एवं बेरोजगारी की समस्या, प्रोद्योगिकी, राजनीतिक व्यवस्था, सार्वभौमिकरण।

Unemployment and Problem of Unemployment, Technology, Political System, Universalization.

प्रस्तावना

वैश्विक व्यवस्था के सार्वभौमिकरण पश्चात रोजगार एंव बेरोजगारी का मुद्दा स्थानीय राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सभी का घ्याान आकर्षित करता रहा है। प्रोद्योगिकी मैं नवीन तत्वौं के समाबेश के पश्चात जहॉ एक ओर रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न हुऐ है उसी के साथ सभी जरुरत मन्दौं तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक गम्भीर चुनौती बनी हुई है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सभी स्तरौ पर प्रभावी कदम उठानें की आवश्यकता है। व्रतीय विश्व के देश उपनिवेश बाद से पूर्व में पीडित होने के कारण रोजगार सम्बन्धी समस्याऔं से गम्भीर रुप से जूझ रहे है।

भारत में बेरोजगार एवं बेरोजगारी की समस्या अनेक स्तरों पर देश की सामजिक आार्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को गम्भीर रुप से प्रभाबित करते रहते हैं। भारत के समस्त निर्वाचनों में बेरोजगार एवं बेरोजगारी की समस्या लगभग सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में सम्लित रहती है । इससे इस समस्या के बिकराल होने को सहज रुप में समझा जा सकता है।

"The Income aspect of Employment is concerned with that part of one's income which is received on the condition that one works."

इस मानदण्ड के अनुसार आय के मानक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनसंख्या के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से प्रस्थापित किया जाता है जिसका कि भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक ही है।

आय के मानदण्ड अथवा मानक को आधुनिक अर्थशास्त्री ''गरीवों की रेखा'' के नाम से भी सम्वोधित करते है।इसका अभिप्रपय यह है कि जनसंख्या का वह भाग जो गरीबी की रेखा से ऊपर है उसको पूर्ण रोजगाररत माना जा सकता है तथा इसके विपरीत जो गरीवी की रेखा से नीचे है बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार रत माना जा सकता है।इस प्रकार आय स्तर एवं गरीबी रेखा के मघ्य विद्यमान विकेंन्द्रण की सीमा के अनुसार अल्प रोजगार का विस्तार भी परिवर्तित होता रहता है।परन्तु गरीबी की रेखा न्यूनतम जीवन स्तर योग्य आय मानक एवं श्रमिकों की आय तथा अभिज्ञान जैसे परिभाषिक दृष्टिकोंणों का मापन इस मानदण्ड के लिए समस्या का विषय है।

जैसा कि उपरोक्त विबेचन से स्पस्ट होता है कि रोजगार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आर्थिक प्रक्रिया में न केवल सक्रिय योगदान तक ही सीमित हेता है अपितु इसका परोक्ष सम्बन्ध इसका परिणाम एवं परिणाम सम्बन्धी उपादेयता से भी है। अतःयह कहना स्वत परिकल्पनीय है कि रोजगार का उत्पादक होना परम् आवश्यक है।जब तक उत्पादन की प्रकिया में रोजगार के माघ्यम से उचित एवं युक्ति संगत मात्रा मैं निर्गत सम्बन्धी योगदान न किया जाय तव तक उसे आर्थिक रोजगार की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।इस प्रकार भौतिक उत्पादकता स्व–रोजगाररत व्यक्तियों के लिए भी एक आधारभूत दृष्टिकोंण निर्धारित है

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्वेश्य बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए इसके समाज एवं देश पर पडने वाले प्रभावों का अघ्ययन करना है। शोध पत्र मैं जीवन निर्वाह स्तर ,गरीवी की रेखा, प्रछन्न बेरोजगारी आदि शब्दावलियों पर चर्चा करते हुए बेरोजगारी की समस्या को भारत के सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

इस प्रसंग में प्रछन्न बेरोजगारी का दृष्टिकोंण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुख्यतया ग्रामीण अंचल में पारिवारिक स्तर पर व्यक्ति रोजगाररत होते हुए भी अनुत्पादक रहता है। इस परिप्रेक्ष में कुछ प्रमुख धारणएं इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है–

1. उक्त प्रछन्न बेरोजगारी की दशा में व्यक्ति के कार्यसेवी होने के कारण उसे ''समय के आधार पर रोजगाररत''माना जायेगा।
2. पारिवारिक आय भोगी होने के कारण आय के आधार पर रोजगाररत माना जायेगा।
3. पारिवारिक उत्पादन में योगदान देनें के कारण उसे उत्पादकता के आधार पर रोजगाररत माना जायेगा।

इस प्रकार आर्थिक प्रसंग में उत्पादकता सम्बन्धी दृष्टिकोंण के दो मुख्य उपागम है।प्रथम उपागम रोजगाररत इकाई की सीमान्त उत्पादकता के शून्य के बराबर होने अथवा न होने के परीक्षण से सम्बन्धित है तथा दूसरे उपागम का सम्बन्ध उत्पादकता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित न करनें वाली रोजगाररत इकाईयों के अतिरेक की वापसी सम्बन्धी अनुमान से सम्बन्धित है।

सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से रोजगार का एक अन्य अर्थ प्रतिष्ठा,सम्मान एवं विशिष्ट अभिज्ञान से भी देखने को मिलता है। इस अभिज्ञान एवं मान्यता का अर्थ यह है कि समाज के सम्पन्न वर्ग में रोजगार का अभिज्ञान प्रतिष्ठा के रूप में लिया जाता है जबकि जीवकोपार्जन करने वाले वर्ग के लिए इसका अभिप्राय पूर्णतया आय के स्त्रोत के रूप में होता है।इस सम्बन्ध में प्रो0 मसूम का कथन है कि–

"Employment can be a factor in self-esteem and indeed in esteem by other,much of course, depends on the class one comes from''

इस प्रकार बेरोजगारी तथा अल्परोजगार के अभिज्ञान एवं मान्यता सम्बन्धी दृष्टिकोण का सम्बन्ध तत्परता के मानदण्ड से होता है।इसी सन्दर्भ में पुनः प्रो0 मसूम ने लिखा है– ´captures the recognition aspect of unemployment under employment ...बेरोजगारी तथा अल्परोजगार की दशा में कार्यविधि एवं आयअर्जन को दृष्टिगत न करते हुए यदि कोई कार्यकरने को तत्पर न हो तो उसे रोजगाररत कहने का अधिकार नहीं है।

उपर्युक्त दोनो दृष्टिकोणो एवं मानदण्डों से रोजगार के अनेक स्वरूपो का अभिज्ञान किया जा सकता है परन्तु इससे यह भी प्रतीत होता है कि बेरोजगारी तथा अल्परोजगार के दृष्टिकोंण एवं मानदण्ड परस्पर अतिक्रमणीय है। अतःइनकी पृथक –पृथक परिभाषा जानना आवश्यकीय प्रतीत होता है।

बेरोजगारी का अभिप्राय व्यक्ति की उस अनैच्छिक निष्क्रियता से है जो कार्यके अभाव में उत्पन्न होती है।

Unemployment has been defiend as involuntary idlennessndue to lack of work''

अतः बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट समयावधि में कार्य करने की इच्छा करते हुए भी किसी कार्य का अवसर नही पाता।

"Unemployed refresh to person belonging to the labour force not doing any work during a specified period but seeking work.

परन्तु अल्प रोजगार की दशा रोजगार एवं बेरोजगारी की एक मध्यवर्ती दशा है नवें श्रम सांख्यकी के अर्न्तराष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अल्प रोजगार उस समय विद्यमान होता हैजब कि रोजगाररत व्यक्ति को पूर्णकालिक कार्य नहीं कर रहे है उनमें अतिरिक्त कार्य करने की योग्यता विद्यमान हो।

निःसन्देह त्रृतीय विश्व में शहरी करण की उग्र प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहरी केंन्द्रो में रोजगार की समस्याओं में अत्यधिक ह्रास हुआ है विश्व के इस अनुभाग में 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की शहरी बेरोजगारी अठवें दशक के अन्त तक देखने को प्राप्त हुई।सामान्यतया विश्व में यह बेरोजगारी 10 से 20 प्रतिशत तक पायी गयी है।नवें दशक में इस बेरोजगारी की औसत दर लगभग 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत

तकबढती दृष्टिगोचर हुईइस प्रकार यह कहा जा सकता है कि त्रृतीय विश्व में मार्क्सवादी राष्ट्रों के अलावा शेष राष्ट्रों में शहरी रोजगार की एक विशेषता यह पाईगयी कि 15 से 24 आयु वर्ग वाले नव युवकों में यह प्रतिशतता औसत से दोगुनी पायी गयी।इसी प्रकार बेरोजगारी के सम्बन्ध में इस त्रृतीय विश्व के अर्न्तगत एक अन्य विशेषता यह भी पायी गयी कि इस विशिष्ट बेरोजगारी में शिक्षित समुदाय का अत्यधिक प्रतिनिधित्व है। परोक्ष रूप में इस त्रृतीय विश्व में विद्यमान शिक्षित बेरोजगारी की भी संज्ञा दी जा सकती हैएक विशेष अनुमान द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि बेरोजगारी एवं शिक्षा में पारस्परिक किस प्रकार का सह–सम्बन्ध है।इसके अनुसार यह पाया गया है कि जिन किशोरो को 6 वर्ष से 11 वर्ष तक विद्यालयी अध्ययन का अनुभव रहा है उनकी प्रतिशतता सर्वाधिक पायी गयी इस श्रेणी के पश्चात प्रायमरी शिक्षा प्राप्त किशोरो की थी जिनको मात्र एक वर्ष से पॉच वर्ष तक का विद्यालयी अनुभव प्राप्त रहा है इस अनुक्रम में अशिक्षित वर्ग तथा माध्यमिक एवं उससे उच्चतर शिक्षा स्तर प्राप्त करने वाले बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व रहा है।

भारत में बेरोजगारी का परिदृष्य–वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की विकराल समस्या है।देश में पिछले तीन दशकों में भारी जनसंख्या में लोग कार्य की तलास में आते रहते है वास्तव में इस प्रकार की स्थिति में बेरोजगारी का रहना स्वाभाविक है।सन 1964 से 1975 के बीच शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक मन्दी के कारण कुछ अतिरिक्त बेरोजगारी पैदा हो गयी लेकिन इस समय सवसे अधिक चिन्ता का विषय ढांचागत बेरोजगारी है।विश्लेषण में बेरोजगारी को दो श्रेणियो में रखा गया है प्रथम शहरी बेरोजगार तथा द्वितीय ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में राजकृष्ण ने लिखा है.

"Unemloyment in india both in terms of magnitude and severalty posses a formidable challenge. Mobilization of resources accelerated growth selective pattern of investment,proper choice of techniques and appropriate spectrum of economic activities in roural and urbon areas with due consideration to capital employment ration and avelivility of complimentary factors of production suggest the multipronged approached required to tackle the problem."

भारतीय नियोजन काल के प्रारम्भ से ही नियोजकों के समक्ष बेरोजगारी तथा अल्पबेरोजगार की समस्यायें एक शाश्वत चुनोती रही है।यह एक प्रतिपादित सत्य है कि ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी का आकार राज्य स्तर पर प्रयुक्त एवं क्रियान्वित होने वाली अनेक योजनायें एवं कार्यक्रमो के बावजूद भी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकराल होता चला जा रहा है।इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय हैकि जब एक ओर तोग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रछन्न बेरोजगारी विद्यमान है,वही दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में सामान्य रूप में बेरोजगारी तथा पिशिष्ट रूप में शिक्षित बेरोजगारी का उग्ररूप देखने को प्राप्त हो रहा है।

1. सामान्य अवस्था में बेरोजगारी ।
2. साप्ताहिक अवस्था में बेरोजगारी।
3. दैनिकअवस्था में बेरोजगारी।

शहरी क्षेत्र में सभी बेरोजगारी प्रत्यक्ष है इस प्रकार की बेरोजगारी व्यक्तिगत रूप से कष्अदायक समझी जाती है क्योंकि इससे सामाजिक स्तर के अर्न्तगत अनेक प्रकार के तनाव पैदा होते है अन्ततःसामाजिक व्यवस्था को खतरा होता है तथा विघटन की ओर उन्मुखता होती है।योजनाकाल के शुरू के वर्षों में शहरो में न केवल बेरोजगारी की संख्या में वृद्वि हुई है बल्कि शहरों में कुल श्रम शक्ति के साथ बेरोजगारो का अनुपात भी ऊपर उठा है।योजना आयोग के अनुसार आठवें दशक के अन्तिम वर्षो में शहरी बेरोजगारी की दर गिरकर 9 प्रतिशत तक आ गई थी।

शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी का ही एक अंग है। यह भारत में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ विभिन्न विद्वान व्यक्तियों द्वारा अलग अलग लगाया जाता है जिसमें मैट्रिक या उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेकार रहते है। सामान्यतः''जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता तथा इच्छानुसार कार्य नहीं मिलता अर्थात उसे रोजगार की तलाशमें इधर उधर भटकना पडता है यही दशा शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है।अन्य सामान्य शव्दों में इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षित व्यक्ति कार्य(रोजगार) तो करना चाहता है परन्तु उसे उसके अनुरूप कार्य नहीं मिलता है। अर्थात वह बेकार रहता है एवं उसकी अपनी शिक्षा या योग्यता का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है।

भारत में जहॉ सन् 1951 में 2 लाख 44 हजार शिक्षित बेरोजगार थे वहॉ सन्1966 में इनकी संख्या 9 लाख 20 हजार और सन् 1972 में 32 लाख 20 हजार तथा सन्1985 में शिक्षित बेरोजगारें की संख्या 47 लाख आंकी गयी है।सातवीं पंचवर्षी योजना के सन 1985 के आरम्भ में 26 प्रतिशत बेरोजगार स्नातक तथा व्यावसायक शिक्षा प्राप्त शिक्षित बेरोजगारों में 74 प्रतिशत मैट्रिक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त थे।यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत में मैट्रिक उत्तीर्ण युवकों के पास कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नही होता इसीलिए वे कोई भी कुशल कार्य करनें में सक्षम तथा दक्ष नहीं होते है। सामान्यतःभारत में शिक्षित बेरोजगारी का मूल कारण वही हैजो देश में सामान्य बेरोजगारी का मूल कारण है।

निष्कर्ष

निष्कर्षत : शोधपत्र से स्पष्ट होता है कि भारत में बेराजगारी एक गम्भीर मुद्दा है । शिक्षा का अभाव , रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन सम्बन्धी समस्याएं कुछ ऐसे कारक है जो बेरोजगारी का कारण बनती है । आय स्तर एवं गरीबी रेखा के मध्य विद्यमान विकेंन्द्रण की सीमा के अनुसार अल्प रोजगार का विस्तार भी परिवर्तित होता रहता है। गरीबी की रेखा न्यूनतम जीवन स्तर योग्य आय मानक एवं श्रमिकों की आय तथा अभिज्ञान जैसे परिभाषिक दृष्टिकोंणों का मापन इस मानदण्ड के लिए समस्या का विषय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *SEN AMARTYA -Empioyment Tecnology anddevelopment ,The oxford university press 1975.p.5*

2. *MASUM MOHAMMAD, Unemployment and underemployment, vivek prakashan Delhi 1996.p.11.*
3. *I.L.O. Employment and economic growth Geneva 1964,p.12*
4. *MASUM MOHAMMAD—Employment and underemployment in agriculture Journal of Agri.economice i.c.a.r.Delhi 1996-97,p.3*
5. *PROF.RAJ KRISHNA; Fundamentals of employment;1960,35*
6. *BAUGM P.R.G.LEYARD AND M.WOODHALL; The causes of graduate unemployment in India London, 1969,p. 234.*
7. *Ninth report of labor statistics Inter National congress, 1997 p.20.*